देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 13.11.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- राज्य मंत्रिमंडल ने देवभूमि परिवार योजना लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी; योजना के तहत प्रदेश के हर परिवार को मिलेगी विशिष्ट पहचान संख्या।
- बच्चों में निमोनिया नियंत्रण के लिये देहरादून से राज्यस्तरीय 'सांस 2025–26' अभियान की शुरुआत।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास कार्यों के लिए लगभग 81 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की।
- और, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. डी.के. असवाल ने राज्य में आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली; भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए समग्र आपदा प्रबंधन नीति तैयार करने के निर्देश दिए।

कैबिनेट

राज्य सरकार ने देवभूमि परिवार योजना लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान कर योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। कैबिनेट ने शहरी निकायों में लोक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों के पर्यवेक्षण के लिए शहरी विकास निदेशालय के अंतर्गत पब्लिक हेल्थ परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन को मंजूरी दी। इसके लिए वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, वित्त नियंत्रक, एम.आई.एस एक्सपर्ट और सहायक लेखाकार के पद सृजित किए जाएंगे।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग स्थापित करने के लिए दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और दो कंप्यूटर प्रोग्रामर पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा और तदर्थ कार्मिकों के विनियमितीकरण तथा भविष्य के लिए कट ऑफ तय करने के लिये मंत्रिमंडलीय समिति बनाने का निर्णय भी लिया गया।

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि केंद्रपोषित बागवानी मिशन के अंतर्गत केंद्रांश में प्राप्त 40 प्रतिशत अनुदान राशि का भुगतान राज्य सेक्टर की मधुग्राम योजना से किया जाएगा। वर्ष 2021–22 और 2022–23 की लंबित 29 लाख चालीस हजार रुपए की राशि भी इसी योजना से दी जाएगी।

सांस 2025–26 शुभारंभ

विश्व निमोनिया दिवस पर देहरादून के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोईवाला में ''निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई– 'सांस 2025–26' अभियान का राज्यस्तरीय शुभारंभ किया गया। यह अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट–

कार्यवाहक मिशन निदेशक अनुराधा पाल ने कहा कि निमोनिया बच्चों की मृत्यु का बड़ा कारण है, जबकि समय पर पहचान और उपचार से इसे रोका जा सकता है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों का नियमित टीकाकरण कराने और लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक, उत्तराखंड, डॉ. रश्मि पंत ने कहा कि सही शिशु देखभाल ही निमोनिया से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। उन्होंने स्तनपान, समय पर पूरक आहार, स्वच्छता और PCV टीकाकरण के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषण किट भी वितरित की गईं। गौरतलब है कि 'सांस 2025–26' अभियान इस वर्ष 12 नवंबर से अगले साल 28 फरवरी तक पूरे राज्य में चलेगा। इस दौरान जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, घर–घर संपर्क, खतरे के लक्षणों की पहचान और सक्रिय मामलों की खोज जैसी गतिविधियाँ की जाएँगी।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अगले एक वर्ष में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया से मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जाए। उन्होंने कहा कि यह अभियान जनसहभागिता के साथ घर–घर तक पहुंचाया जाएगा।

स्वास्थ्य परामर्श

केन्द्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चेस्ट क्लीनिक स्थापित करने का आह्वान किया गया है। ये क्लीनिक वायु प्रदूषण के दौरान प्रतिदिन कम से कम दो घंटे खुले रहने की सलाह दी गई है। परामर्श में लोगों को सड़कों और भारी यातायात वाले क्षेत्रों, उद्योगों के आसपास के क्षेत्रों और निर्माण तथा विध्वंस स्थलों जैसे उच्च वायु प्रदूषण वाले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। लोगों को सुबह और देर शाम बाहर टहलने, दौड़ने, जॉगिंग करने और शारीरिक व्यायाम करने से भी बचने को कहा गया है।

ट्रॉफी भेंट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिव, उद्योग विनय शंकर पाण्डेय ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 के तहत मिले टॉप अचीवर्स पुरस्कार की ट्रॉफी भेंट की। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्योग सचिव को प्रदान किया गया था।

उत्तराखण्ड को यह सम्मान व्यवसाय प्रवेश, निर्माण परमिट सक्षमकर्ता, पर्यावरण पंजीकरण, निवेश सक्षमकर्ता और श्रम विनियमन सक्षमकर्ता जैसे पाँच सुधार क्षेत्रों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर मिला है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की व्यवसाय सुगमता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान राज्य के सतत प्रयासों का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने सतत और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, और ये सुधार निवेश बढ़ाने के साथ पर्यावरणीय संतुलन और समान विकास को भी मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन का प्रमुख माध्यम बन रहा है और व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 में शीर्ष राज्यों में स्थान मिलने से निवेशकों का विश्वास और बढ़ेगा।

स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास कार्यों के लिए लगभग 81 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए यह स्वीकृति अलग–अलग मदों के तहत दी गई है। मिसिंग लिंक फंडिंग कार्यक्रम के तहत चमोली जिले में गोपीनाथ मंदिर मार्ग को स्थानीय शैली में बनाने के लिए नौ करोड़ नवासी लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन–शहरी के दूसरे चरण में कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए 40 प्रतिशत केंद्रांश के रूप में तैंतीस करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है।

राज्य योजना के तहत बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र में धौली नदी पर 120 मीटर स्पान के पैदल झूला पुल के निर्माण के लिये लगभग दस करोड़, धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के थत्यूड–मराड मोटर मार्ग के लिए तीन करोड़ रुपए से अधिक और अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में तल्ली चम्याड़ी से रणतखाल मोटर मार्ग के अवशेष कार्य के लिए पांच करोड़ चौसठ लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, देहरादून के रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में टाइप–2 के 120 आवास बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है।

आपदा प्रबंधन तैयारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. डी.के. असवाल ने उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का दौरा कर आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य की भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए समग्र आपदा प्रबंधन नीति तैयार करने के निर्देश दिए।

डॉ. असवाल ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में विकास और आपदा प्रबंधन के बीच संतुलन आवश्यक है। उन्होंने ऐसी दूरदर्शी नीति बनाने पर जोर दिया जो विकास के साथ आपदा जोखिम को कम करने पर भी समान ध्यान दे। उन्होंने कहा कि नीति में वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित योजनाएं, जोखिम मानचित्रण, संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण नियंत्रण, पारंपरिक ज्ञान और तकनीकी नवाचारों का संतुलित उपयोग शामिल होना चाहिए।

उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता बताई और कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसमें पूरा सहयोग

करेगा। उन्होंने एक मजबूत डाटा सेंटर स्थापित करने का सुझाव दिया, जहां सभी विभागों और संस्थानों से प्राप्त आंकड़े एकीकृत रूप से उपलब्ध हों और आपदा जोखिमों का विश्लेषण करने में मदद मिल सके। डॉ. असवाल ने ऐसे मॉडल गांव विकसित करने का भी सुझाव दिया जिन्हें आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाकर अन्य क्षेत्रों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके।

अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए वन अधिकारियों और खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड को 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता की मेजबानी मिलना राज्य के लिये गर्व का विषय है।

श्री धामी ने बताया कि इस बार 42 टीमों के 3 हजार 390 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 700 से अधिक महिला खिलाड़ी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड खेल और पर्यावरण संरक्षण का अग्रदूत बना है। प्रदेश का 71 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, जिससे उत्तराखण्ड देश का 'ऑक्सीजन बैंक' और 'वॉटर टावर' बनता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत स्टेडियम परिसर में अपनी माताओं के नाम एक पौधा लगाने की अपील की।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर....

- दिल्ली ब्लास्ट में चल रही कार्रवाई को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है – डॉ उमर ने ही किया था धमाका, 6 दिसंबर को दिल्ली में 26–11 जैसे हमले की थी साजिश। हिन्दुस्तान लिखता है – षड्यंत्रकर्ताओं ने जनवरी में की थी लाल किले की रेकी। नवोदय टाइम्स लिखता है – निशाने पर थे आयोध्या–काशी।
- धामी कैबिनेट में लिए गए निर्णय को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है – उत्तराखंड के हर परिवार की बनेगी आईडी, योजनाओं से मिलेगा लाभ। दैनिक जागरण लिखता है – उत्तराखंड के हर परिवार को मिलेगी विशिष्ट पहचान, आपदा मुआवजा राशि बढ़ाई।
- शराब कारोबारियों व बिल्डरों पर आय विभाग की छापेमारी को सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है – देहरादून में शराब कारोबारियों और बिल्डरों पर आयकर छापे।